www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 348 | जौनपुर, शनिवार, 08 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

आत्मनिर्भर चिकित्सा-तकनीक से वैश्विक भागीदार बन रहा भारत - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा–तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। पीएम मोदी ने कहा कि घरेलू विनिर्माण, आयात पर निर्भरता में कमी और पीएलआई तथा मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी योजनाओं के जरिए भारत किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित एक विश्वसनीय वैश्विक चिकित्सा–तकनीक भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर साझा पोस्ट में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा–तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला है। इसमें

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में देश की क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया गया है। लेख में चिकित्सा–तकनीक क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयासों को रेखांकित किया गया है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने से चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता कम करने और देश में मजबूत विनिर्माण आधार तैयार करने में मदद मिल रही है। पीएम मोदी के अनुसार, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी सरकारी पहल भारत के चिकित्सा–तकनीक क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का बढ़ता चिकित्सा– तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता से देश में चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा कि इन प्रयासों के चलते भारत एक विश्वसनीय वैश्विक चिकित्सा–तकनीक भागीदार के रूप में लगातार उभर रहा है।

संक्षिप्त खबरें

अभिजीत दीपके का सुरक्षा में तैनात पीएसआई से विवाद

मुंबई, (एजेंसी)। मुंबई में सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके के आवास की सुरक्षा में तैनात एक पीएसआई को लेकर विवाद सामने आया है। दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उनके घर आने वाले लोगों के साथ कथित तौर पर रूखा व्यवहार कर रहा था और लोगों को उनसे मिलने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इस घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।वायरल वीडियो में अभिजीत दीपके एक पुलिस अधिकारी से बहस करते दिखाई दे रहे हैं। वह पुलिसकर्मी से सवाल करते हैं कि उनके घर आने वाले लोगों को अंदर आने से क्यों रोका जा रहा है। दीपके ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी से कहा कि वह उनके निजी आवास में लोगों से मिलने को लेकर पुलिस की ओर से किसी तरह का नियंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे।वीडियो में दीपके पुलिसकर्मी से यह कहते सुनाई देते हैं कि जब वह खुद लोगों को अपने घर आने के लिए कह रहे हैं तो उन्हें रोकने की जरूरत क्या है। उन्होंने पुलिस के व्यवहार की तुलना दिल्ली पुलिस से करते हुए सवाल उठाया कि उनके घर आने–जाने वाले लोगों को लेकर पुलिस को निर्देश देने का अधिकार किसने दिया है।सीजेपी संयोजक ने इस दौरान राज्य सीआईडी के कुछ कर्मचारियों पर भी नजर रखने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि कुछ लोग सादे कपड़ों में उनके आवास के आसपास मौजूद थे और उनके बारे में जानकारी जुटा रहे थे। दीपके ने दावा किया कि एक रिपोर्टर ने उन्हें बताया कि कुछ संदिग्ध लोग उनके घर के पास देखे गए थे। उनके मुताबिक, पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर उन्होंने खुद को सीआईडी से जुड़ा बताया। दीपके ने एक कथित व्हाट्सएप ग्रुप का नाम 'भ्पज `चतंल' बताते हुए दावा किया कि संबंधित कर्मचारी वहां अपनी रिपोर्ट भेज रहे थे। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। एक अन्य वायरल वीडियो में दीपके फोन पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शिकायत करते दिखाई देते हैं। उन्होंने सुरक्षा में तैनात च्ैप् के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए उसे हटाने की मांग की।

'मिथिला मखवाना' की बढ़ी विदेशों में मांग, बिहार के किसानों के लिए खुल रहे नए अवसर – पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बिहार के प्रसिद्ध जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) टैग प्राप्त 'मिथिला मखाना' ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को बताया कि पहली बार बिहार से 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना का समुद्री मार्ग के जरिए ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया है। उन्होंने कहा कि मिथिला मखाना की बढ़ती वैश्विक मांग बिहार के किसानों के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस उपलब्धि की जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत के जीआई–टैग वाले मिथिला मखाना ने वैश्विक बाजार में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के सहयोग से जीआई टैग वाले 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना को बिहार से ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह मखाना सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदा गया था। इस पहल से जुड़े किसानों को बाजार भाव की तुलना में लगभग 18: अधिक लाभ मिला है। इससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उन्हें अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिला है। गोयल ने कहा कि मिथिला मखाना की बढ़ती वैश्विक मांग बिहार के किसानों के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। उन्होंने इसे राज्य के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

शहरी सहकारी बैंकों को मिलेगा आधुनिक डिजिटल सुरक्षा कवच – अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज (8 अगस्त 2026) मुंबई के फोर्ट स्थित शारदा सदन में नेशनल अर्बन को–ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नवीन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और महाराष्ट्र के जिला संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। अमित शाह इसके बाद ठैम् इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में

आयोजित 'सहकार नव–क्रांति' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहेंगे। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान छन्ब्थ्क्ब् और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया जाएगा। इसके जरिए शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, तकनीकी दक्षता और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। अमित शाह शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ राष्ट्रव्यापी सेवा बंडल के तहत कोर बैंकिंग सेवा और उससे जुड़ी अन्य सेवाओं की शुरुआत की जाएगी।

गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समारोहों की मेजबानी करने वाले जिलों के लिए विकास अनुदान दोगुना किया

गांधीनगर, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने गांधीनगर के बाहर राज्य–स्तरीय गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गुजरात राज्य स्थापना दिवस समारोहों की मेजबानी करने वाले जिलों के लिए विकास अनुदान दोगुना कर दिया है। राज्य द्वारा मंजूर किए गए संशोधित प्रावधानों के तहत अधिकतम आवंटन 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा 6 अगस्त को जारी एक प्रस्ताव के मुताबिक, इन राज्य–स्तरीय कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए चुने गए जिलों को अब ग्रामीण, शहरी और नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ज्यादा फंड मिलेगा। संशोधित नीति का उद्देश्य आधिकारिक राज्य समारोहों के आयोजन के साथ–साथ बुनियादी ढांचे और

नागरिक विकास को बढ़ावा देना है।राजधानी के बाहर बड़े राज्य–स्तरीय राष्ट्रीय समारोह आयोजित करने की परंपरा 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। ऐसा पहला कार्यक्रम 15 अगस्त 2003 को पाटन में स्वतंत्रता दिवस समारोह था। इस पहल का मकसद आधिकारिक राष्ट्रीय समारोहों को गुजरात के अलग–अलग हिस्सों में ले जाना था, साथ ही यह सुनिश्चित करना था कि मेजबान जिलों को भी इन कार्यक्रमों से जुड़े विकास प्रोजेक्ट्स का फायदा मिले। संशोधित प्रावधानों के तहत, मेजबान जिले के जिला विकास अधिकारी को ग्रामीण विकास के लिए 5 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पहले 2.5 करोड़ रुपये थे। मेजबान जिले की नगरपालिकाओं को भी जिला कलेक्टर के जरिए शहरी विकास के लिए 5 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि पहले यह अनुदान 2.5 करोड़ रुपये था।जहां कार्यक्रम नगर निगम की सीमा के भीतर आयोजित किया जाता है, वहां नगर निगम आयुक्त 5 करोड़ रुपये तक के विकास अनुदान के हकदार होंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में प्रदान किए संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में हिस्सा लिया और संत कबीर हथकरघा पुरस्कार तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इस अवसर पर भारत की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में चार स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा सदियों से भारत की सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें देश की असाधारण विविधता दिखाई देती है और क्षेत्रीय विशिष्टताओं को संरक्षित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हथकरघा क्षेत्र रोजगार, महिला सशक्तीकरण, कला–संस्कृति और प्रकृति–प्रेम को बढ़ावा देता है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम और

आत्मनिर्भरता की भावना से भी जुड़ा रहा है। राष्ट्रपति ने बताया कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं और उद्योगों को बढ़ावा देना तथा देश के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करना था। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में केंद्र सरकार 2015 से हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख मानव–केंद्रित उदाहरण बनने की क्षमता रखता है। महत्वपूर्ण हथकरघा क्लस्टरों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है और इन प्रयासों से भारतीय हथकरघा की अंतरराष्ट्रीय छवि भी मजबूत हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक और नवाचारी डिजाइनों के साथ बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली युवा उद्यमी हथकरघा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। सरकारी योजनाओं और संस्थानों के जरिए युवाओं को सक्रिय सहयोग एवं मार्गदर्शन दिए जाने की जरूरत है। युवा उद्यमी, डिजाइनर और स्टार्टअप पारंपरिक शिल्प को आधुनिक ट्रेंड्स, ब्रांड्स और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़कर नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

विश्व की धार्मिक राजधानी बन रही अयोध्या,फिर भी तेज रफ्तार रेल सेवाओं का इंतजार

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या आज विश्व के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्रों में अपनी पहचान बना रही है।प्रतिदिन देश के विभिन्न राज्यों के साथ–साथ विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जहां सड़क और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, वहीं रेल सेवाओं में अपेक्षित बढ़ोतरी अब भी नहीं हो सकी है।वर्तमान में अयोध्या से लंबी दूरी के लिए कुछ पुरानी ट्रेनें जैसे दून एक्सप्रेस, जम्मू तवीदृसियालदह एक्सप्रेस और साबरमती एक्सप्रेस संचालित हैं, लेकिन इनमें यात्रा अवधि अधिक होने के कारण यात्रियों को काफी समय लगता है। आधुनिक दौर में, जब देश के कई शहर वंदे भारत और अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों से जुड़ चुके हैं।तब विश्व भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुकी रामनगरी अभी भी तेज गति वाली लंबी दूरी की रेल सेवाओं का इंतजार कर रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अयोध्या से माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, उज्जैन महाकाल, तिरुपति बालाजी, विंध्याचल, ज्वाला देवी, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और देश के अन्य प्रमुख धार्मिक एवं महानगरों के लिए सीधी सुपरफास्ट ट्रेनें शुरू की जानी चाहिए। इससे यात्रियों का समय बचेगा, यात्रा आसान होगी और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। अयोध्या से माता वैष्णो देवी, कामाख्या धाम (कटरा), हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन (महाकाल), तिरुपति बालाजी, विंध्याचल और ज्वाला देवी जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों के लिए वंदे भारत एवं अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। जब अयोध्या विश्वभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुकी है, तो यहां की रेल सेवाएं भी उसी स्तर की होनी चाहिए। श्रद्धालुओं का समय बचे, यात्रा सरल हो और रामनगरी देश के हर प्रमुख शहर से तेज रेल नेटवर्क द्वारा जुड़ सके।

आयुष सिंह यादव ने असिस्टेंट कमाडेंट व जूनियर इटेलीजेंस ऑफिसर के पद पर चयनित होकर क्षेत्र का बढ़ाया मान

संवाददाता देश की उपासना मड़ियाहूं, जौनपुर। हिनौती निवासी आयुष सिंह यादव, सुपुत्र अच्छेलाल यादव, प्रा. वि. रामपुर खास प्रधानाध्यापक, व माता उर्मिला देवी अध्यापिका के पुत्र बने असिस्टेंट कमांडेंट पद पर नियुक्ति होने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। आयुष की इस उपलब्धि से उनके परिवार के बड़े पिता जी श्री राम सागर यादव, चाचा साहब लाल यादव पंचायत मित्र, प्रेम सागर यादव अध्यापक तथा श्री मोती लाल यादव से.नि. भारतीय रेलवे विभाग (मेठ) और परदादा भगेलू यादव से.नि. रेलवे विभाग अपने कुल के चौथी पीढ़ी का होनहार छात्र NIT मोतीलाल नेहरू से B.Tech. के बाद UPSC के असिस्टेंट कमांडेंट पद पर 2025 बैच AIR– 203 रैंक हासिल की। इनके प्रेरणा स्रोत रहे, जगदीश चंद यादव सी. ओ. वाराणसी व साहब लाल यादव प्रबंधक जनता जनार्दन ई.का. मेंहदी व प्रधानाचार्य, अवधेश कुमार यादव सुभाष ई. का. कटवार जौनपुर साथ–साथ हिनौती और मड़ियाहूं क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। आयुष सिंह यादव ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उनकी सफलता की जानकारी मिलते ही परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों और शुभचिंतकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। क्षेत्रवासियों ने कहा कि आयुष की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उनकी उपलब्धि ने यह साबित किया है कि कड़ी मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण से सफलता हासिल की जा सकती है। परिजनों ने आयुष के उज्ज्वल भविष्य और देश की सेवा में सफल कार्यकाल की कामना की।

चयन प्रक्रिया निष्पक्ष हो, किसी एथलीट के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए – खेल मंत्री मांडविया

'नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शनिवार को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एनएसएफ) कॉन्क्लेव 2026 की अध्यक्षता की। कॉन्क्लेव में खेल प्रशासन को मजबूत करने, खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देने और आगामी बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा पर विशेष जोर दिया गया। कॉन्क्लेव में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 के तहत नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अनुपालन की स्थिति, खेल संस्थाओं में सुशासन तथा एशियन गेम्स 2026, लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए एनएसएफ की तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। डॉ. मांडविया ने कहा कि खेल इकोसिस्टम में हर हितधारक के लिए एथलीटों का हित और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता होना

चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है कि किसी भी एथलीट के साथ अन्याय न हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ओपन सेलेक्शन ट्रायल पर्यवेक्षक की मौजूदगी में कैमरे पर रिकॉर्ड किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एथलीटों को खेल के मैदान पर बनाए रखने और देश में मजबूत लीग संस्कृति विकसित करने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को पूरे वर्ष एथलीटों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय खेलों से डोपिंग खत्म करने के लिए व्यापक रणनीति की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार एंटी–डोपिंग इकोसिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक बदलावों पर काम कर रही है। मांडविया ने कहा कि डोपिंग के खतरे से निपटने के लिए केवल एथलीटों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं है।

संपादकीय

संस्थाओं के ऊपर से लोगों का भरोसा समाप्त

एक एक करके इस देश की हर संस्था की साख खत्म होती जा रही है और संस्थाओं के ऊपर से लोगों का भरोसा समाप्त है, और इसका नया आयाम कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की ओर से जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन शुरू हुआ घटनाक्रम भी है। ध्यान रहे देश दो चीजों पर भरोसे से चलता है। पहली चीज है इलेक्शन और दूसरी चीज है एग्जामिनेशन। इन दोनों पर भरोसे का संकट है। एक के बाद एक चुनाव जीतने की जिद में भाजपा ने ऐसे काम किए, जिनसे लोगों का भरोसा घटा। यह सिर्फ विपक्षी पार्टियों का मामला नहीं है। आम लोगों के मन में भी यह धारणा बैठ गई है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। यह धारणा बनवाने में भाजपा का इकोसिस्टम भी समान रूप से जिम्मेदार है। श्मोदी है तो मुमकिन हैय का नारा भी इस धारणा को मजबूत करता है। भाजपा इकोसिस्टम के लोग अमित शाह की लार्जर दैन लाइफ छवि बनाने के लिए ऐसा प्रचार करते हैं कि वे जहां हाथ डाल देंगे वहां कामयाबी मिलेगी। रील्स और वीडियो बना कर प्रचारित कराया जाता है कि वे जहां चाहेंगे वहां चुनाव जिता देंगे। पश्चिम बंगाल की जीत के बाद यह प्रचार तेज हुआ है। लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीट पर आ गई थी। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और दिल्ली व बिहार में जैसे वह जीती है उससे भी लोगों के मन मे यह धारणा बैठी कि कुछ भी हो जाए भाजपा जीतेगी। इससे चुनाव आयोग के साथ साथ चुनाव की विश्वसनीयता प्रभावित हुई। भाजपा के लोग मजाक में ही सही लेकिन इस धारणा का प्रचार करते हैं कि वोट किसी को दीजिए, वह जाएगा भाजपा के खाते में और चुनाव कोई जीते सरकार भाजपा बनाएगी। इन बातों से समूची चुनाव प्रक्रिया संदेह के घेरे में आई है। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से मीडिया के एक समूह ने प्रदर्शनकारियों को विलेन बना कर सरकार का एजेंडा चलाया उसने मीडिया की विश्वसनीयता को और कम किया। इससे पहले दूसरे प्रदर्शनों में भी ऐसा ही होता था परंतु किसान हों या शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी वे श्जेन जीय की तरह मुखर या सामने से प्रतिवाद करने वाले नहीं थे। लेकिन युवाओं ने प्रतिवाद किया और यह देखने को मिला कि उन्होंने मुख्यधारा की मीडिया को लगभग समूचे आंदोलन से बाहर रखा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही आंदोलन की जगह बना दिया। कई मीडियाकर्मियों के साथ जंतर मंतर पर जो हुआ ।

विचारों की पत्रकारिता के नायक

संजय

राजेंद्र माथुर की पूरी जीवन यात्रा एक साधारण आम आदमी की कथा है। वे इतने साधारण हैं कि असाधारण लगने लगते हैं। उन्होंने जो कुछ पाया, एकाएक नहीं पायाय संघर्ष से पाया, नियमित लेखन से पाया और अपनी रचनाशीलता से पाया। इसी संघर्ष की वृत्ति ने उन्हें असाधारण पत्रकार और संपादक बना दिया। राजेंद्र माथुर का पत्रकारीय व्यक्तित्व इस बात से तय होता है कि आखिर उनके लेखन में विचारों की गहराई कितनी है। अपने अखबार को ऊंचाइयों पर ले जाने का उनका संकल्प कितना गहरा है और हमारे समय के प्रश्नों के जवाब तलाशने तथा नए सवाल खड़े करने की कितनी प्रश्नाकुलता संबंधित व्यक्ति में है। राजेंद्र माथुर का संपादकीय और पत्रकारीय व्यक्तित्व इस बात की गवाही देता है कि वे असहज प्रश्नों से मुंह नहीं चुराते, बल्कि उनसे दो–दो हाथ करते हैं। वे सवालों से जूझते हैं और उनके सही एवं प्रासंगिक उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। भाषाके संसाधन वे सही मायने में पत्रकारिता में विचारों के एक ऐसे प्रतीक पुरुष बनकर सामने आए, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से एक बौद्धिक उत्तेजना का सृजन किया और हिंदी को एक ऐसी भाषा तथा विराट अनुभव–संसार दिया, जिसकी प्रतीक्षा में वह सालो से खड़ी थी। इस मायने में राजेंद्र माथुर की उपस्थिति अपने समय में एक कद्दावर पत्रकार–संपादक की मौजूदगी है। वरिष्ठ पत्रकार श्री सूर्यकांत बाली के मुताबिक,"माथुर साहब जैसा बोलते थे, वैसा ही लिखते थे। वे धाराप्रवाह, विचार–परिपूर्ण और रूपक–अलंकृत बोलते थे, तो धाराप्रवाह, विचार–परिपूर्ण और रूपक–अलंकृत लिखते भी थे।" ऐसे में कहा जा सकता है कि राजेंद्र माथुर के पत्रकारीय एवं संपादकीय व्यक्तित्व में एक बौद्धिक आकर्षण दिखता है। उनके लेखन में भारत–जिज्ञासा, भारत–अनुराग और भारत–स्वप्न पूरी समग्रता में प्रकट होते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र ने लिखा है कि "राजेंद्र माथुर में बौद्धिकता और सच्चरित्रता का असाधारण संगम था, इसीलिए वे हिंदी पत्रकारिता में शिखर स्थान पा सके। वे असाधारण शैलीकार थे। अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक होने के बावजूद उनकी हिंदी लेखन शैली बिंब–प्रधान थी। उनके मुहावरे अपने होते थे। उनमें अभिव्यंजना की अद्भुत शक्ति थी। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में वे एक शैलीकार के रूप में याद किए जाएंगे।" राजेंद्र माथुर एक श्रेष्ठ संपादक थे। उनकी उपस्थिति ही श्नईदुनियाश और श्नवभारत टाइम्सश को एक ऐसा समाचार पत्र बनाने में सफल हुई, जिस पर हिंदी पत्रकारिता को नाज है। श्नवभारत टाइम्सश में श्री माथुर के सहयोगी रहे श्री विष्णु खरे ने लिखा है कि, "राजेंद्र माथुर महान संपादक होने का अभिनय करने की कोई जरूरत महसूस नहीं करते थे। दरअसल, लिबास से लेकर बोलचाल तक उनकी कोई बनावटी शैली या लहजा नहीं थाय वे अपने मामूलीकरण में विश्वास करते थे, वैशिष्ट्य में नहीं। उनकी संपादकीय आदेशों या हुक्मों से नहीं, एक गुणात्मक तथा नैतिक विकिरण से चलती" राजेंद्र माथुर का पत्रकारीय व्यक्तित्व बेहद प्रेरक था। आज की पत्रकारिता और मीडिया संस्थानों में घुस आई तमाम बुराइयों से उनका व्यक्तित्व एकदम अलग था। संपादक की जैसी शास्त्रीय परिभाषाएं बताई गई हैं, श्री माथुर उन पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। उनके समकक्ष पत्रकारों की राय में, जिस समय वे दिल्ली में श्नवभारत टाइम्सश जैसे बड़े अखबार के संपादक थे, वे सत्ता के लाभ उठा सकते थे। आज की पत्रकारिता में जिस तरह पत्रकार एवं संपादक सत्ता से लाभ लेकर मंत्री से लेकर राज्यसभा की सीटें ले रहे हैं, श्री माथुर भी ऐसे प्रलोभनों के पास जा सकते थे। किंतु उन्होंने तमाम चर्चाओं के बीच इससे खुद को बचाया। पत्रकार विष्णु खरे अपने लेख में इस बात की पुष्टि भी करते हैं। सही मायने में राजेंद्र माथुर एक ऐसे संपादक के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने अपने पत्रकारीय व्यक्तित्व को वह ऊंचाई दी जिसके लिए पीढ़ियां उन्हें याद कर रही हैं। उनके पत्रकारीय व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी हिंदी पत्रकारिता को लेकर उनकी चिंताएं हैं। वे हिंदी पत्रकारिता के एक ऐसे संपादक थे, जो लगातार यह सोचते रहे कि हिंदी पत्रकारिता का विचार–दारिद्र्य कैसे दूर किया जाए और कैसे हिंदी में एक संपूर्ण अखबार निकले तथा उसे व्यापक लोकस्वीकृति भी मिल सके। श्नवभारत टाइम्सश के कार्यकारी संपादक रहे स्व. सुरेंद्र प्रताप सिंह ने उनकी इन चिंताओं को निकटता से देखा था। वे लिखते हैं, "माथुर साहब का गहन इतिहास–बोध, शुद्ध श्रद्धा और उससे उत्पन्न गरिमामय अतीत की मरीचिका पर आधारित हिंदी पत्रकारिता की कमजोर आधारभूमि के बारे में उन्हें बार–बार सचेत करता रहता था। वे भूतकाल के वायवीय स्वर्णिम अतीत में जीने वाले नहीं थे। वे स्वप्नदर्शी थे और अपने सपनों की उदात्तता के साथ उन्होंने कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। हिंदी पत्रकारिता का वर्तमान परिदृश्य उन्हें बार–बार विचलित तो कर देता था, लेकिन एक कुशल अभियात्री की तरह उन्होंने अपने जहाज की दिशा को क्षणिक प्रलोभनों के लिए किसी अन्य रास्ते पर डालने के बारे में क्षणिक विचार भी नहीं किया।

एफसीआरए बिल पर हल्ला मचा रहे विपक्षी दलों और ईसाई संगठनों को मार्को रुबियो का बयान सुनना चाहिए

नीरज

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक को लेकर देश में तो इस समय व्यापक बहस छिड़ी ही हुई है, साथ ही इसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहले स्वयं यह कह चुके हैं कि किसी भी देश में विदेशी फंड से संचालित संस्थाओं को वहां की संप्रभु सरकार के समानांतर व्यवस्था नहीं चलानी चाहिए और उन्हें मेजबान देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए। इसके बावजूद अमेरिकी सांसद राइली मूर भारत के प्रस्तावित कानून की आलोचना कर रहे हैं। दूसरी ओर, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि प्रस्तावित संशोधन को पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू नहीं किया जाएगा। इन घटनाक्रमों के बीच मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भारतीय कानूनों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में एफसीआरए के तहत पंजीकृत सक्रिय संगठनों की संख्या घटी है, लेकिन विदेशी चंदे का प्रवाह बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024–25 में 16,200 संगठनों को लगभग 22,963 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान प्राप्त हुआ। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त या समाप्त भी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि केवल वैध पंजीकरण रखने वाले संगठनों को ही विदेशी धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा लाए गए संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है, नवीनीकृत नहीं होता या संस्था स्वयं उसे छोड़ देती है, तो विदेशी धन से निर्मित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक ष्नामित प्राधिकरणष की व्यवस्था की जाएगी। यदि बाद में संस्था का पंजीकरण बहाल हो जाता है तो संबंधित संपत्तियां और अप्रयुक्त विदेशी योगदान वापस कर दिए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार का तर्क है कि यह व्यवस्था किसी नए अधिकार का सृजन नहीं, बल्कि पहले से मौजूद प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने का प्रयास है। वहीं प्रस्तावित संशोधन को लेकर कुछ चर्च संगठनों ने आशंकाएं भी व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि कानून की कुछ धाराएं अत्यधिक कठोर हैं और उन्हें संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से विभिन्न चर्च संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने अमित शाह के साथ बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं का विस्तार से जवाब भी दिया है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून किसी विशेष धर्म, समुदाय या विचारधारा को निशाना नहीं बनाता। एफसीआरए के प्रावधान सभी विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले संगठनों पर समान रूप से लागू होते हैं। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी संपत्ति का मामला आता है तो उसके धार्मिक स्वरूप को कानूनन सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही, नामित प्राधिकरण के आदेश अंतिम नहीं होंगे और उनके विरुद्ध न्यायालय में अपील का अधिकार भी उपलब्ध रहेगा। उधर, इस पूरे विवाद का अंतरराष्ट्रीय पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अमेरिकी सांसद राइली मूर ने आरोप लगाया कि यह कानून चर्चों और ईसाई संस्थाओं के खिलाफ है। हालांकि स्वयं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले वर्ष यह कहा था कि विदेशी सहायता कार्यक्रम मेजबान देशों की सरकारों के समानांतर नहीं चलने चाहिए और विदेशी वित्तपोषित संस्थाओं को संबंधित देश की नीतियों और कानूनों के अनुरूप काम करना चाहिए। यही कारण है कि भारत के संदर्भ में उठ रही आलोचना पर दोहरे मापदंड का प्रश्न भी सामने आया है। देखा जाये तो लोकतंत्र में किसी भी कानून पर बहस और समीक्षा का अधिकार सभी को है, लेकिन भारत की संप्रभुता

और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। यदि कोई संगठन विदेशी चंदे के सहारे पूरी पारदर्शिता और भारतीय कानूनों का पालन करते हुए जनकल्याण का कार्य करता है, तो उसके लिए इस कानून से घबराने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत, जिन संस्थाओं या तत्वों ने विदेशी धन का उपयोग नियमों से इतर गतिविधियों, अपारदर्शी वित्तीय लेन–देन या भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाने के प्रयासों के लिए किया है, उनके लिए स्वाभाविक रूप से चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि प्रस्तावित संशोधन निगरानी, जवाबदेही और कानूनी अनुपालन को और मजबूत करने का प्रयास करता है। मोदी सरकार का कहना है कि यह कानून किसी धर्म या समुदाय को लक्षित नहीं करता, बल्कि विदेशी अंशदान के नियमन और पारदर्शिता के लिए समान रूप से लागू होगा। ऐसे में यदि विदेशी फंडिंग के नाम पर नियमों की अनदेखी करने वालों की मुश्किलें बढ़ती हैं, तो इसे कानून के दायरे में जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। बहरहाल, संसद में होने वाली चर्चा के बाद कानून का अंतिम स्वरूप तय होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि विदेशी धन के उपयोग पर प्रभावी निगरानी और राष्ट्रीय हितों की रक्षा किसी भी संप्रभु राष्ट्र की वैधा जिम्मेदारी है।

एमपी में कुशवाहा वोट बैंक की ताकत के आगे झुकी भाजपा

नीरज

मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा राजनीतिक संदेश दिया है, जिसकी गूंज अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर के एक विवादित बयान से शुरू हुआ विवाद आखिरकार सार्वजनिक माफी तक पहुंच गया। भाजपा की आंतरिक समीक्षा में यह संकेत मिलने के बाद कि कुशवाहा समाज की नाराजगी पार्टी की हार का बड़ा कारण बनी, तोमर ने स्वयं आगे आकर अपने शब्द वापस लिए और कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी इस समाज का अपमान करने की नहीं सोचा। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब 31 जुलाई को मुरैना में भाजपा के जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा के निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा समाज को संबोधित करते हुए कहा कि यह समाज बीच–बीच में ष्गुलाटी खाता रहाष और इसी कारण उसने अपनी ष्विश्वसनीयता को खंडितष किया। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय ऐसा था जब कुशवाहा समाज भाजपा का मजबूत समर्थक माना जाता था और भाजपा ने उस दौर में भी समाज को सम्मान दिया, जब अन्य राजनीतिक दल उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने पूर्व नेता कालीचरण कुशवाहा को टिकट दिए जाने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। हालांकि, कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक भूचाल आ गया। कुशवाहा समाज के विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों ने इस टिप्पणी को पूरे समाज की राजनीतिक निष्ठा पर सवाल बताकर तीखी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने भी इसे तुरंत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का अपमान बताते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती और उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर से सार्वजनिक माफी की मांग की। इस बीच, दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा दीं। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशीष तिवारी को 6,016 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। भाजपा की आंतरिक समीक्षा में यह बात सामने आई कि दतिया के लगभग 12 प्रतिशत मतदाता रहे कुशवाहा समाज का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर खिसक गया, जिसने चुनावी परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। इसके बाद भाजपा संगठन ने हार की व्यापक समीक्षा शुरू की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ नेताओं और चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की, दतिया जिला इकाई को भंग किया गया, समीक्षा समितियां गठित की गईं और संगठनात्मक कमजोरियों के साथ–साथ संभावित अंदरूनी असंतोष की भी जांच शुरू हुई। इसी राजनीतिक आत्ममंथन के बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा समाज के नाम हस्ताक्षरित पत्र जारी कर अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि कमलेश कुशवाहा के घर आयोजित कार्यक्रम पारिवारिक वातावरण में था और उसी संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि उनका और कुशवाहा समाज का रिश्ता परस्पर पूरक है तथा उन्होंने जीवनभर इस समाज का सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे। यदि उनके शब्दों से किसी की भावना आहत हुई है तो वह अपने शब्द वापस लेते हैं और इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। उनका यह बयान भाजपा के भीतर बढ़ी राजनीतिक बेचैनी और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, यह पूरा घटनाक्रम केवल एक बयान और माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की बदलती सामाजिक–राजनीतिक राजनीति का संकेत भी देता है। राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग आधी हिस्सेदारी रखता है और कुशवाहा समाज इस वर्ग का एक प्रभावशाली हिस्सा माना जाता है। ग्वालियर–चंबल अंचल के मुरैना, दतिया, भिंड और ग्वालियर जैसे जिलों से लेकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र तक इस समाज की उल्लेखनीय उपस्थिति है। कई विधानसभा सीटों पर यह समाज जीत–हार तय करने की क्षमता रखता है। विशेष रूप से दतिया जैसी सीट पर, जहां कुशवाहा मतदाता लगभग 12 प्रतिशत हैं, किसी भी दल के लिए इस समाज की अनदेखी राजनीतिक जोखिम बन सकती है। यही कारण है कि भाजपा ने पिछले दो दशकों में ओबीसी सामाजिक समीकरणों के केंद्र में कुशवाहा समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया। दूसरी ओर कांग्रेस भी अब इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। पार्टी ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के नेतृत्व में बूथ स्तर तक व्यापक अभियान चलाया, जिसका असर दतिया उपचुनाव में दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश में केवल एक बड़ा वोट बैंक नहीं, बल्कि एक प्रभावी ष्स्विंग फैक्टरष भी है। यदि समाज को सम्मान, पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी का संदेश मिलता है तो वह किसी भी दल के साथ मजबूती से खड़ा हो सकता है। लेकिन उपेक्षा या अपमान की भावना पैदा होने पर उसका रुख तेजी से बदलने की क्षमता भी रखता है। यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर के ष्गुलाटीष वाले बयान के बाद भाजपा को सार्वजनिक रूप से डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। बहरहाल, दतिया उपचुनाव ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मध्य प्रदेश की आगामी राजनीतिक लड़ाई केवल नेताओं के भाषणों या चुनावी नारों से नहीं जीती जाएगी। सामाजिक सम्मान, प्रतिनिधित्व और ओबीसी वर्गों के साथ मजबूत संवाद आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगा। नरेंद्र सिंह तोमर की सार्वजनिक माफी इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुशवाहा समाज अब केवल एक वोट बैंक नहीं, बल्कि सत्ता का समीकरण बदलने वाली निर्णायक राजनीतिक ताकत बन चुका है।

भारत में बढ़ती असमानता और सिकुड़ते अवसर

राजेश

भारत राष्ट्रीय समाचार भारत की आबादी में युवाओं की संख्या 29 से 30 फीसदी के बीच होने का अनुमान है। चीन सहित कई देशों की तरक्की के पीछे युवाओं की अहम भूमिका रही है। अब बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से ऐसे देशों में काम करने वाली आबादी का प्रतिशत घटा है। उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट का एक कारण यह भी है। इस दृष्टि से भारत की बहुत अनुकूल स्थिति है। भारत को हमेशा चमकीली संभावनाओं का देश माना जाता है। पुराने दौर में उसके लिए सोने की चिड़िया विशेषण का इस्तेमाल होता था। उसमें दुनिया की बड़ी ताकत के बतौर उभरने की क्षमता रही है। लेकिन वर्तमान स्थिति खोए हुए अवसरों की अनंत कथा के रूप में तब्दील हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से देश में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। राजनीतिक सत्ता के समान संपत्ति और साधन चंद लोगों के हाथों में सिमट गए हैं। नीतियों और प्राथमिकताओं में कुछ अमीरों को ज्यादा अहमियत मिल रही है। विश्व बैंक के आंकड़े और कई विशेषज्ञों के निष्कर्ष हालात की सही तस्वीर पेश करते हैं। जानकारी छिपाने और तोड़–मरोड़कर तथ्य पेश करने में माहिर सरकार भी कई बार सच बता देती है। भारत ने आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार का झुकाव समाजवाद और पूर्व सोवियत संघ की व्यवस्था की तरफ था। सरकार ने कई उद्योगों की बुनियाद रखी और बड़े बांध बनाए। विशुद्ध पूंजीवाद के पैरोकार कई अर्थशास्त्री देश की अपेक्षाकृत धीमी विकास दर के लिए इस मॉडल को जिम्मेदार मानते हैं। खासतौर से 2014 के बाद तो देश की तमाम समस्याओं का ठीकरा नेहरू के कार्यकाल पर फोड़ने का सिलसिला चल पड़ा है। बहरहाल, पं. नेहरू के दौर में बने एक विराट सार्वजनिक क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए। कुछ नए शहर अस्तित्व में आए, अर्थव्यवस्था को सहारा मिला और अवसरों में आम लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी थी। एक बेहद पिछड़े देश ने विकास की दौड़ में बड़े देशों से होड़ करने का सपना देखा था।विकास के नेहरूवादी मॉडल में आगे जाकर कई सरकारों ने बदलाव किए हैं। लेकिन आर्थिक गैरबराबरी नए शिखर स्पर्श कर रही है। यहां हम आय, संपत्ति, उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़ों से विकास की वास्तविक स्थिति का काफी हद तक मूल्यांकन कर सकते हैं। पेरिस इकानॉमिक्स स्कूल की विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत में कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति और आय के जमा होने का स्तर चरम पर पहुंच गया है। वह दुनिया के सबसे ज्यादा असमान देशों की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय आय के 58 प्रतिशत हिस्से पर टॉप दस प्रतिशत लोगों का कब्जा है। दूसरी ओर सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे 50 प्रतिशत लोगों के हिस्से में सिर्फ 15 प्रतिशत आमदनी आई है। कुल राष्ट्रीय आय के 40 प्रतिशत के मालिक एक फीसदी लोग हैं। विश्व बैंक की जुलाई 2026 में जारी एक रिपोर्ट में भारत को निम्न मध्यम आय की अर्थव्यवस्था बताया गया है। यह दर्जा 2009 से चल रहा है। मतलब पिछले 15–16 वर्षों से स्थिति लगभग यथावत है। भारत के महाशक्ति बनने की संभावनाएं वर्षों से जताई जा रही हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद तो विश्व गुरु, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था सहित कई दावे जोर–शोर से किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों पर संदेह बढ़ा है। इंडियन एक्सप्रेस में अभी हाल प्रकाशित सी राजामोहन के लेख में दो विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि भारत में बड़ी ताकत बनने की कई खूबियां हैं पर इतनी नहीं कि वह दुनिया की व्यवस्था को आकार दे सके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकार ब्रेंडन सिम्स ने अपनी नई किताब– द रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर्स में भारत को फ्रांस, जर्मनी और जापान के साथ महाशक्ति बनने की कगार पर खड़े देशों की सूची में रखा है। वे लिखते हैं यदि अगले दशक में भारत का कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ब्रिटेन, जापान और जर्मनी से अधिक हो जाता है तब भी वह अमेरिका और चीन से बहुत पीछे तीसरे स्थान पर रहेगा। फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में एक लेख में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के माइकेल बेकले की दलील है, विश्व राजनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका तो बनी रहेगी लेकिन अपनी कई घरेलू कमजोरियों के कारण उसके वास्तविक महाशक्ति बनने की संभावना नहीं है।ये घरेलू कमजोरियों कौन सी हैं? 2014 के बाद धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई ने राजनीतिक दलों के साथ औद्योगिक, व्यावसायिक हलकों में डर पैदा किया है। उद्योगपति निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री कभी चेतावनी तो कभी सवाल पूछने के अंदाज में कहते हैं, समझ में नहीं आता है उद्योगपति निवेश करने से पीछे क्यों हट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में प्राइवेट सेक्टर का निवेश जीडीपी के 11 प्रतिशत पर आ गया है। वहीं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह 14 प्रतिशत था। यह स्थिति उस वक्त है जब मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर 2019 में 30प्रतिशत से घटाकर 22प्रतिशत कर दी।अब उद्योगपति सरकार के फैसलों, उसकी नीतियों पर सवाल उठाने की बजाय उसकी तारीफ करने में लगे रहते हैं। हर बजट का जमकर स्वागत होता है। कुछ साल पहले तक उद्योगपति राहुल बजाज सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते थे। फरवरी 2022 में उनके निधन के बाद उद्योग क्षेत्र से ऐसी कोई असरदार आवाज सामने नहीं आई है। कॉरपोरेट सेक्टर जोखिम भी नहीं उठा रहा है। उसका ध्यान किराए, ब्याज, शेयर बाजार के लाभांश और वायदा बाजार जैसी रेंटियर गतिविधियों पर ज्यादा है। 2012–13 से 2023–24 के आयकर रिटर्न के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है, व्यावसायिक गतिविधियों से कंपनियों की कुल कर योग्य आय 57.3प्रतिशत से गिरकर 54.3प्रतिशत पर आ पहुंची थी। न्यूयॉर्क के थिंक टैंक रोडियम ग्रुप और ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट का निष्कर्ष है, मैन्युफैक्चरिंग में भारत आगे नहीं बढ़ सका है। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट और अमेरिका से व्यापार युद्ध ने दूसरे देशों के लिए आर्थिक फायदा उठाने के मौके बनाए हैं। लेकिन भारत के मुकाबले इस स्थिति को वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको जैसे देशों ने ज्यादा भुनाया है। पश्चिमी देशों की कई कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग

चीन से हटाकर इन देशों में स्थानांतरित कर दी है। निजी क्षेत्र के निवेश में गिरावट के बीच कुछ अमीरों की संपत्ति तेज रफ्तार से बढ़ रही है। दो उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच आगे निकलने की जबर्दस्त होड़ है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार 2026 के मध्य में 8.84 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ अडानी भारत के सबसे अमीर शख्स थे। 2021 में उनकी संपत्ति 7.12 लाख करोड़ रुपए थी। उन्होंने पांच साल से कम समय में अपनी संपत्ति में ढाई लाख करोड़ रुपए का इजाफा कर लिया है। अडानी ने भारतीय अमीरों के सिंहासन पर लंबे समय से आसीन मुकेश अंबानी को पीछे हटा दिया है। 2021 में अंबानी की संपत्ति लगभग 8.84 लाख करोड़ रुपए थी। यह 2026 में घटकर 8.65 लाख करोड़ रुपए पर आ गई। असमानता की एक और तस्वीर इन आंकड़ों में देखिए। बीते कुछ वर्षों में कुछ भारतीयों की आय और संपत्ति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल में वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक आय वाले लोगों की संख्या 2021–22 के 142 से बढ़कर 2025–26 में 576 हो गई थी। एक अरब 40 करोड़ की आबादी में यह संख्या मुट्ठी भर कही जाएगी। दूसरी और बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें अच्छा जीवन बिताने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2025 में नियमित कर्मचारियों का औसत सालाना वेतन 2.7 लाख रुपए (22 हजार 699 रुपए मासिक) था। वहीं आकस्मिक कामगार का औसत दैनिक वेतन सिर्फ 453 रुपए रहा।

18 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, सह–आरोपी बरी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने 18 वर्ष पुराने हत्या के मामले में शुक्रवार को आरोपी प्रेमचंद सरोज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में सह–आरोपी विनोद सरोज को आरोपों से बरी कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार, नेवढ़िया थाना क्षेत्र निवासी वादी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 2 मार्च 2008 की रात उसके पिता राजदेव मौर्य रोज की तरह भोजन करने के बाद गुतवन बाजार स्थित अपनी हार्डवेयर की दुकान पर सोने चले गए थे। आरोप है कि देर रात अज्ञात हमलावर दुकान पर पहुंचे और ध ारदार हथियार से उनकी हत्या कर फरार हो गए। अगली सुबह जब परिजन दुकान पर पहुंचे तो राजदेव मौर्य का शव खून से लथपथ मिला। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान प्रेमचंद और विनोद सरोज का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रेमचंद उर्फ पप्पू सरोज को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं दूसरे आरोपी विनोद सरोज के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर अदालत ने उसे दोषमुक्त करने का आदेश दिया।

कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 23 पुलिसकर्मियों पर परिवाद, कोर्ट ने थानाध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में खुटहन थाना क्षेत्र के चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी रवि यादव की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। रवि यादव की मां अमरावती देवी की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने थाना खेतासराय से रिपोर्ट तलब की थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पुलिस का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर अगली तारीख पर स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। परिवादिनी अमरावती देवी, निवासी सोंधी (खेतासराय), ने अपने अधिवक्ता समर बहादुर यादव के माध्यम से एसओजी प्रभारी, थाना खेतासराय के तत्कालीन प्रभारी, थाना लाइन बाजार के तत्कालीन प्रभारी सहित 23 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध परिवाद दायर किया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि एक मई 2026 को हुए आजाद बिंद हत्याकांड में रवि यादव को आरोपी बनाया गया था। बाद में वह दिल्ली चला गया, जहां से 23 मई को पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जौनपुर लाया। आरोप है कि 25 मई की रात गोरारी तिराहे के पास फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या कर दी गई। परिवाद में यह भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम में सीने में गोली लगने की पुष्टि हुई और घटना की निष्पक्ष जांच कराए बिना कथित मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि पहले पुलिस अध ीक्षक और मुख्यमंत्री को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली गई।इस मामले में शुक्रवार को जानकारी देते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने बताया कि अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों की अनुपस्थिति पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए संबंधित थानाध यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 14 अगस्त निर्धारित की है।

ठाकुरगंज में बंद पड़ी धान मिल में सांड की हत्या, तीन हिरासत में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के न्यू हैदरगंज स्थित एक बंद पड़ी धान मिल में गौवंश (सांड) का गला काटकर हत्या किए जाने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही ठाकुरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक तथा फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने घटना के शीघ्र खुलासे के लिए विशेष टीमों का गठन करते हुए जांच तेज कर दी है। मामले में तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त 2026 को न्यू हैदरगंज स्थित एक बंद पड़ी धान मिल में गौवंश (सांड) का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल को सुरक्षित कर फोरेंसिक प्रक्रिया शुरू कराई गई। पशु चिकित्सक एवं फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य संकलित किए। इसके साथ ही घटनास्थल की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी पूरी की गई।पशु चिकित्सक द्वारा परीक्षण के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए गौवंश के शव को चिन्हित स्थान पर दफन कराया गया। घटना के संबंध में ठाकुरगंज थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।घटना के अनावरण के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके अलावा तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है तथा स्थानीय लोगों से भी विस्तृत पूछताछ की गई। अब तक की जांच और उपलब्ध वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन एवं निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। जांच में सामने आने वाले सभी तथ्यों, वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ के आध ार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटना में संलिप्त पाए जाने वाले सभी दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अफसरों के रवैये से हाईकोर्ट नाराज, सरकार को भरना होगा 50 हजार रुपये का हर्जाना

लखनऊ, (संवाददाता)। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता से संबंधित मामले में अधिकारियों की सुस्ती पर राज्य सरकार पर 50000 रुपये का हर्जाना लगाया है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश उदय प्रताप सिंह की ओर से वर्ष 2019 में दायर जनहित याचिका पर दिया। याचिका में प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता का मुद्दा उठाया गया था। 16 दिसंबर 2025 को अदालत ने इस मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा था। अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि विशेष सचिव की अध यक्षता वाली जिस समिति को शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता देने या वापस लेने पर विचार करना था, वह बैठक अब तक नहीं हो पाई। संबंधित अधिकारी आठ माह में एक भी दिन बैठक करने के लिए नहीं निकाल पाए। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट से कार्यवाही का ब्योरा पेश करने को चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। इस पर न्यायालय ने मांगा समय 50 हजार रुपये हर्जाने के साथ समय दे दिया। कहा कि हर्जाने के साथ समय अफसरों की उस सुस्ती और असंवेदनशीलता के लिए दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ये कार्यवाही लंबित है। न्यायालय ने कहा, हमें नहीं पता कि ये कार्यवाही कब तक लंबित रहेगी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह मामला 7 सितंबर को इस न्यायालय के समक्ष आएगा, जब संबंधित विशेष सचिव निर्णय के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

जलकल विभाग के 14 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान

लखनऊ, (संवाददाता)।नगर निगम लखनऊ के जलकल विभाग में वर्षों तक सेवाएं देने के बाद 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सम्मान में गुरुवार को ऐशबाग स्थित जलकल मुख्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में महापौर सुषमा खर्कवाल ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और विभाग व शहर के प्रति उनके योगदान की सराहना की।कार्यक्रम में 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए कुल 14 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें लेखाधिकारी पंकज कुमार सोती, गैंगमैन त्रिवेणी, सरोज कुमारी, शिव कुमार सिंह एवं चांदी प्रसाद त्रिपाठी, सीवर सफाई कर्मचारी पुन्नू और हरीश, चौकीदार हरि प्रकाश, पम्प ऑपरेटर दिलीप कुमार श्रीवास्तव, इन्द्र देव प्रसाद, राना प्रताप सिंह एवं सुरेश कुमार, लिपिक श्रेणी–द्वितीय राम जी मिश्रा तथा प्रधान लिपिक प्रदीप कुमार सक्सेना शामिल रहे।इस अवसर पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि जलकल विभाग के कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल के दौरान पूरी।

हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां तेज, चार लाख से अधिक तिरंगों की सिलाई पूरी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. के निर्देशन में जनपद में 'हर घर तिरंगा अभियान' 2026–27 को सफल बनाने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अभियान के तहत जिले के सभी विकास खंडों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगा झंडों की सिलाई में जुटी हैं। इसी क्रम में उपायुक्त (स्वतः रोजगार), जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला मिशन प्रबंधक ने विकास खंड धर्मापुर, मुफ्तीगंज और केराकत में स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित तिरंगा सिलाई केंद्रों का निरीक्षण किया। धर्मापुर में वैष्णवी महिला स्वयं सहायता समूह दशरथपुर और उत्कर्ष महिला स्वयं सहायता समूह धर्मापुर, जबकि मुफ्तीगंज में यमुना आजीविका स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत निशान तथा पयहारी बाबा महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत कुंडी की महिलाएं तिरंगा झंडों की सिलाई करती मिलीं। जनपद में इस वर्ष पांच लाख तिरंगा झंडों की सिलाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक चार लाख से अधिक तिरंगों की सिलाई पूरी की जा चुकी है। इस कार्य में जिले के विभिन्न विकास खंडों के करीब 300 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं जुटी हैं। तिरंगा सिलाई के कार्य से महिलाओं को रोजगार के साथ अतिरिक्त आय का अवसर भी मिल रहा है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तिरंगा झंडों की सिलाई का कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद के अन्य विभाग भी अपनी आवश्यकता के अनुसार आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से तिरंगा झंडों की सिलाई करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे 'हर घर तिरंगा अभियान' को गति मिलने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनकी आजीविका भी मजबूत होगी।

प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के लिये छात्रों को किया प्रेरित

यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। जनविकास महासभा एवं सोक्ट द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज एस डी मेमोरियल इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के प्रति प्रेरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जनविकास महासभा के अध्यक्ष पंकज

कुमार तिवारी ने विद्यार्थियों को बताया की वर्तमान समय में हम सभी को अपनी प्रतिभा के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी अपने टैलेंट के अनुरूप अपना करियर का चुनाव करते हैं उनके जीवन में सफल होने का प्रतिशत ज्यादा होता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए की पढ़ाई के साथ–साथ अपने अंदर के टैलेंट को भी आगे बढ़ाएं इसी क्रम में कार्यशाला में शामिल हुए बच्चों उनके अंदर की प्रतिभा को बताने के लिए प्रेरित किया गया जिसमें बच्चों ने बढ़–चढ़ के हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को पर्यावरण एवं जल संरक्षण तथा नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में जनविकास महासभा के महामंत्री अजय यादव सहित स्कूल प्रबंधक एस.एस.प्रसाद, प्रधानाचार्य प्रज्ञा मिश्रा, विशाल कनौजिया, सुमन कनौजिया, संतोष उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे।

हर घर तिरंगा अभियान-2026 को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जनपद में 'हर घर तिरंगा अभियान–2026' को व्यापक जनभागीदारी एवं उत्साह के साथ सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में देर सायं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों, विभागवार दायित्वों, प्रचार–प्रसार, तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता दिवस समारोह सहित अन्य गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। अभियान के अंतर्गत जनपद में 09 अगस्त से 17 अगस्त, 2026 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि 'हर घर तिरंगा अभियान' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जन–जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के प्रत्येक कार्यक्रम को निध ारित समय–सारिणी के अनुसार पूरी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ आयोजित किया जाए तथा इसमें अधिक से अधिक नागरिकों, युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, स्वयंसेवी संगठनों एन सी सी छात्र छात्राए, माई भारत वॉलेंटियर एवं जनप्रतिनिध ियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। बैठक में अभियान के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 09 से 15 अगस्त तक विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 'तिरंगा–प्रेरित कला गतिविधि' आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र एवं 'वंदे मातरम से संबंधित गतिविधियां कराई जाएंगी। संबंधित गतिविधियों की फोटोग्राफी कराकर निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड भी की जाएगी। इसी क्रम में 10 से 15 अगस्त तक जनपद के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा थीम आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, चौराहों एवं अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण कराया जाएगा, जिससे पूरे जनपद में देशभक्ति का वातावरण निर्मित हो। अभियान के अंतर्गत 11 से 15 अगस्त तक प्रमुख सार्वजनिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। 14 अगस्त को तिरंगा कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों एवं उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में तिरंगा गान, देशभक्ति गीत तथा 'वंदे मातरम्' देशभक्ति गायन कराया जाएगा। साथ ही स्कूली बैंड, पुलिस बैंड, आदि द्वारा देशभक्ति के गीतों की धुनें प्रस्तुत की जाएंगी। 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत भारत विभाजन विभीषिका से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके माध्यम से विभाजन के दौरान घटित घटनाओं एवं उससे जुड़ी स्मृतियों को जनसामान्य तक पहुंचाया जाएगा तथा नई पीढ़ी को इतिहास एवं उससे जुड़े अनुभवों से अवगत कराया जाएगा। बैठक में तिरंगा रैली आयोजित किए जाने की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। तिरंगा रैली में बाइक रैली के साथ ही विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसमें विद्यार्थी, युवा, सरकारी अधिकारी–कर्मचारी, पुलिसकर्मी, महिला स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठन, एनसीसीध्एन.एस.एस छात्र–छात्राए, माई भारत वालेंटियर एवं अन्य नागरिक शामिल होंगे। जिलाधिकारी ने रैली के दौरान यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। इसी प्रकार 14 अगस्त को प्रातः 08:30 बजे से तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। यात्रा के दौरान 'वंदे मातरम का सामूहिक गायन कराया जाएगा तथा विद्यार्थियों, युवाओं, सरकारी अध िकारियों–कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के सदस्यों, महिला स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों सहित विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद के प्रत्येक घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थल पर तिरंगा फहराया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम स्तर से लेकर नगरीय क्षेत्रों तक अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करते हुए प्रत्येक परिवार को अभियान से जोड़ा जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा एवं सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। तिरंगा निर्धारित नियमों एवं सम्मान के साथ ही फहराया जाए तथा किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न होने पाए। अभियान के अंतर्गत 09 से 17 अगस्त तक 'तिरंगा सेल्फी' गतिविधि भी आयोजित की जाएगी। नागरिकों द्वारा तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर तथा 'वंदे मातरम्' गायन के वीडियो को ींतहींतजपतंदहं.बवउ वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अभियान की प्रत्येक गतिविध ि की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई जाए और निर्धारित पोर्टल www-harghartiranga-com पर फोटो एवं वीडियो अपलोड किए जाएं। साथ ही जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि तिरंगा यात्रा एवं जुलूस के दौरान चिन्हित स्थानों पर पेयजल एवं सूक्ष्म जलपान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यात्रा के दौरान ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी तथा साउंड, बैंड, फ्लैग आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। यातायात व्यवस्था सुचारु रखने तथा प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने–अपने दायित्वों का समय से निर्वहन करें तथा आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। प्रत्येक कार्यक्रम में संबंधित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति एवं व्यवस्थाओं की निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अभियान से संबंधित सभी गतिविध ियों का आयोजन निर्धारित तिथियों पर समय से कराया जाए और कार्यक्रमों की जानकारी एवं फोटो–वीडियो निध ारित माध्यमों पर अपलोड करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि 'हर घर तिरंगा अभियान–2026' में पूरे उत्साह के साथ सहभागी बनें और अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत करने में अपना योगदान दें।

प्रसव कराने के तुरंत बाद ओपन सर्जरी कर महिला के दिल के दो वॉल्व बदले, बचाई जच्चा-बच्चा की जान

लखनऊ, (संवाददाता)। संजय गांधी पीजीआई के चार विभागों के डॉक्टरों ने गर्भवती महिला की दो जटिल सर्जरी कर जच्चा–बच्चा की जान बचाने में कामयाबी हासिल की है। सिजेरियन से प्रसव कराने के तुरंत बाद ओपन सर्जरी कर महिला के दिल के दो वॉल्व बदले गए। 2. 1 किलो वजन की जन्मी बेटी और पहली बार मां बनी महिला दोनों स्वस्थ हैं। संस्थान के डॉक्टरों के मुताबिक प्रदेश में इस तरह का पहला और देशभर में चौथा मामला है। मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ (एमआरएच) विभाग की डॉ. नीता सिंह के मुताबिक महिला को गर्भावस्था के 32वें हफ्ते में गंभीर रूप से सांस लेने में तकलीफ और धड़कन तेज होने की समस्या बढ़ने पर परिजन संस्थान लेकर आए। जांच में पता चला कि महिला दिल के वॉल्व की गंभीर रूमैटिक हार्ट डिजीज से पीड़ित थी। एमआरएच, कार्डियोलॉजी और सीवीटीएस विभाग के डॉक्टरों ने 21 जुलाई को उसके दो जटिल ऑपरेशन किए। सबसे पहले सुरक्षित प्रसव कराया गया। इसके तुरंत बाद ओपन हार्ट सर्जरी से महिला के दोनों वॉल्व बदल दिए। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों में वह सामान्य स्थिति में आ गई। संस्थान के निदेशक पद्मश्री डॉ. आरके धीमन ने जटिल ऑपरेशन करने वाली टीम को बधाई दी है। एमआरएच विभाग की डॉ. नीता सिंह, डॉ. मोनाली वी. खेरगाडे, एचओडी डॉ. मंदाकिनी प्रधान, रेजिडेंट डॉ. अपराजिता, और रेजिडेंट डॉ. हर्षित खरे व एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. अमित रस्तोगी, डॉ. लाराब शेख और रेजिडेंट डॉ. श्रद्धा गांगेले, डॉ. सरबानी घोष, डॉ. शिवेंद्र प्रताप सिंह।

ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों पर लखनऊ पुलिस का विशेष प्रशिक्षण

लखनऊ, (संवाददाता)। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके प्रति संवेदनशील एवं सम्मानजनक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कमिश्नरेट लखनऊ ने गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित संगोष्ठी सदन में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में 120 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एवं नियमावली, 2020 के प्रावधानों के साथ व्यवहारिक और कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई।यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अमित कुमावत के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। वहीं पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा ममता रानी तथा सहायक पुलिस उपायुक्त महिला अपराध शाहिदा नसरीन ने कार्यक्रम के सफल संचालन की जिम्मेदारी निभाई।कार्यशाला में कमिश्नरेट के सभी थानों पर तैनात अतिरिक्त निरीक्षक, वरिष्ठ उपनिरीक्षक, वर्ष 2023 बैच के उपनिरीक्षक तथा पिंक बूथ पर नियुक्त महिला आरक्षियों सहित कुल 120 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया।

100 वर्ष पुराना मकान ढहा, एक ही परिवार के छह लोगों की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली वार्ड में करीब 100 वर्ष पुराना मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में सो रहे थे। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन, पुलिस और राहत–बचाव दल ने तत्काल अभियान चलाया, लेकिन छह लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी।जानकारी के अनुसार, लगातार हो रही बारिश के कारण मकान की दीवारें कमजोर हो गई थीं। देर रात अचानक पूरा मकान ढह गया, जिससे घर के अंदर सो रहे सभी सदस्य मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने तेज आवाज सुनकर तत्काल राहत कार्य शुरू किया और पुलिस तथा प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और राहत–बचाव दल मौके पर पहुंचे तथा मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला।इस भीषण हादसे में महुली निवासी नितिन श्रीवास्तव (24 वर्ष), प्रमोद श्रीवास्तव (45 वर्ष), रीता श्रीवास्तव (42 वर्ष), माधुरी (24 वर्ष), माधव (2 वर्ष) और छह माह के मासूम बाबू की मौत हो गई। परिवार के सदस्य अमन श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

महापौर की अध्यक्षता में एक ही मंच पर सुनी जाएंगी नागरिकों की समस्याएं

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम लखनऊ नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले शसंपूर्ण समाधान दिवसश का आयोजन इस माह 7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को करेगा। यह कार्यक्रम महापौर सुषमा खर्कवाल की अध यक्षता में आयोजित होगा, जिसमें शहरवासी नगर निगम से संबंधित अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। नगर निगम के अनुसार, संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जल निकासी, सफाई व्यवस्था, सड़क, स्ट्रीट लाइट, गृहकर, अतिक्रमण सहित नगर निगम से संबंधित अन्य सभी समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए नगर निगम के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एक ही मंच पर उपस्थित रहेंगे, जिससे नागरिकों को अलग–अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

डाक विभाग वॉटरप्रूफ लिफाफे में भाइयों तक पहुंचाएगा स्नेह का धागा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। रक्षाबंधन का पर्व इस बार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। डाक विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है स भाई–बहन के प्रेम का प्रतीक यह त्योहार देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जाता है।बदलते समय में लोग नौकरी व अन्य कारणों से अपने घरों से दूर रहते हैं। जिससे कई बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं पहुंच पातीं।ऐसे में डाक विभाग ने उनके लिए बड़ी राहत दी है इस प्रेम के धागे को पहुचाने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफा उपलब्ध करवा रहा है।10 रू के लिफाफे से स्पीड पोस्ट एवं पार्सल के माध्यम से देश विदेश में बहनों की राखी सुरक्षित भाई तक पहुंचाएगा।रक्षाबन्धन भाई बहन के प्रेम का पर्व है बहनें अपने भाइयों को रक्षाबन्धन भेजकर जो मधुर प्रेम का एहसास करती है।इसीलिए डाक विभाग में रक्षाबंधन पर बहना को ष्सुकन्या समृद्धि खातेष का उपहार देने की अपील करते हुए अयोध्या मण्डल के अधीक्षक डाकघर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस रक्षाबंधन के पर्व पर सभी भाई अपनी बहन के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सुकन्या समृद्धि खाता का उपहार भेंट करें।साथ ही श्री श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि बहन की राखी स्नेह बारिश में तो भीग ही जाती हैं लेकिन डाक विभाग ने ऐसी व्यवस्था की है कि बहन जो राखी अपने भाईयों को भेजेंगी उस बरसात का पानी असर नही करेगा।भाई दूर शहरों मे रहता है तो बहने डाक विभाग से राखी भेजती है अक्सर लिफाफा कागज का और कमजोर होने के कारण फट जाता है कई बार बारिश के पानी से राखियां भीग जाने के कारण नष्ट भी हो जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि डाक विभाग वाटरप्रूफ आकर्षक रंगीन लिफाफा बहनों को मुहैया कराने के साथ साथ सरल एवं सुगम तरीके से तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेगा।मण्डल कार्यालय में रक्षाबन्धन पर्व के अवसर एवं सुकन्या समृद्धि अभियान को गति देने के लिए अपने मातहतों के साथ बैठक भी किया इस दौरान अयोध्या मण्डल के अधीक्षक डाकघर ने बताया कि डाक विभाग के अनुसार, राखी और मिठाई भेजने के लिए बहनें स्पीड पोस्ट, और पार्सल सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं। यह अयोध्या अकबरपुर प्रधान डाकघर सहित मण्डल के सभी उप डाकघरों में राखी का वाटरप्रूफ लिफाफा उपलब्ध करा दिया गया है।रक्षाबन्धन भाई बहन के प्रेम का पर्व है बहनें अपने भाइयों को रक्षाबन्धन भेजकर जो मधुर प्रेम का एहसास करती है सभी भाई इस राखी पर बहना को दें ष्सुकन्या समृद्धि खातेष का उपहार, मात्र 250 रुपये में खाता खुलवाकर अपनी बहन के भविष्य को सँवारने का अपील किया ।

प्रशासन को पहले से थी जानकारी,फिर भी नहीं टला खूनी संघर्ष,पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र की मोतीगंज चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत जोहन, मजरा चितई का पुरवा में लंबे समय से चल रहा जमीन विवाद शनिवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी–डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैरिंग्टनगंज और बीकापुर में कराया जा रहा है।पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाद की जानकारी प्रशासन को पहले से थी। राजेश मिश्रा ने उपजिलाधिकारी और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि पड़ोसी उनकी भूमि पर जबरन नींव खोदकर अवैध निर्माण कराने का प्रयास कर रहे हैं।बताया जाता है कि एसडीएम के निर्देश पर लेखपाल मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को निर्माण कार्य न करने की हिदायत भी दी। इसके बावजूद आरोप है कि दूसरे पक्ष ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया।पीड़ित पक्ष का कहना है कि निर्माण शुरू होने की सूचना तत्काल पीआरबी और मोतीगंज चौकी पुलिस को दी गई।पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन केवल औपचारिक कार्रवाई कर लौट गई और विवाद का स्थायी समाधान नहीं कराया। इसके कुछ ही घंटों बाद दोनों पक्ष आमने–सामने आ गए और विवाद हिंसक झड़प में बदल गया।ग्रामीणों का आरोप है कि यदि पुलिस समय रहते सख्ती से निर्माण कार्य रुकवाती और विवादित स्थल पर निगरानी रखती, तो यह हिंसक घटना टाली जा सकती थी। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस और राजस्व विभाग की कार्यशैली को लेकर तरह–तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है।जब प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस को पहले से विवाद की जानकारी थी, शिकायतें दर्ज थीं, लेखपाल निरीक्षण कर चुका था और पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। अब पूरे प्रकरण में लोगों की निगाह पुलिस और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। यदि पुलिस की कार्यशैली या किसी स्तर पर लापरवाही की जांच होती है, तो कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं।

तिरंगा यात्रा की तैयारी को लेकर प्रेस क्लब सिविल लाइन में पत्रकारों की बैठक संपन्न

अयोध्या।शनिवार को तिरंगा यात्रा के संबंध में प्रेस क्लब सिविल लाइन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक में 14 अगस्त को निकलने वाली तिरंगा यात्रा पर चर्चा की गई।चर्चा के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव, सचिव जेपी सिंह,सुबोध श्रीवास्तव,रूपेश

श्रीवास्तव,समीर शाही,नरेंद्र मिश्रा,आकाश सोनी,राजेंद्र दूबे,स्कंद दास,राजेश कुमार श्रीवास्तव,करन प्रजापति, महेंद्र,वैभव श्रीवास्तव, क्षितिज साधवानी, गुलजार खान, राजू सिंह सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे।बैठक मे प्रेस क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव,सुबोध श्रीवास्तव, रुपेश श्रीवास्तव,सहित अन्य पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किये।बैठक में तिरंगा यात्रा का जगह–जगह स्वागत को लेकर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए।

5 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली अवैध हथियार बरामद

गोरखपुर, (संवाददाता)। देवरिया के भाटपाररानी थाना क्षेत्र में गोवंश तस्करी के मामले में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गुरुवार देर रात लार और भाटपाररानी पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर

भाटपाररानी पुलिस चनुकी मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भाग निकला। सूचना मिलते ही लार पुलिस ने खरवनिया मोड़ पर घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपी बाइक मोड़कर भागने लगा, लेकिन फिसलकर गिर गया। इसके बाद उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान अजहर अंसारी पुत्र अहमद अंसारी, निवासी मटियरा जगदीश, थाना लार के रूप में हुई। वह भाटपाररानी थाने में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध लार थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में एक और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

वित्त मंत्री ने सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जनपद की सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराई जाएं। बैठक में जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी सहित लोक निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जनपद में 18 सड़कों पर हॉट मिक्स का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है, जबकि 4 सड़कों पर सीसी निर्माण कार्य भी लंबित है। इस पर वित्त मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए सभी लंबित कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। बैठक में आर्थिक स्वीकृति प्राप्त सड़क परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। इस दौरान यह भी अवगत कराया गया कि वाजिद अली तिराहे से जामा मस्जिद तक सड़क निर्माण कार्य अगले सप्ताह से प्रारंभ किया जाएगा। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने बैठक में मा० मंत्री को अवगत कराया कि सभी लंबित परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है तथा संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने जलकल विभाग को पाइपलाइन लीकेज की समस्या पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच त्वरित सूचना आदान प्रदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाएं साझा करने के भी निर्देश दिए। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने नगर क्षेत्र में संचालित सड़क एवं अन्य विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपनी–अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर वित्त मंत्री ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

देशभक्ति की लहर को तेज करने के लिए यूथ कनेक्ट तिरंगा रैली का हुआ भव्य आयोजन

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव' 'हरदोई' शनिवार को हरदोई स्पोर्ट्स स्टेडियम में देश भक्ति की लहर तेज करने के लिए यूथ कनेक्ट तिरंगा

रैली का शुभारंभ स्पोर्ट्स स्टेडियम से हुआ। सर्वप्रथम क्रीडाधिकारी मंजू शर्मा ने जिलाधिकारी महोदय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया,।

नवनियुक्त मण्डलायुक्त ने अपना पदभार संभाला

प्रयागराज, (संवाददाता)। नवनियुक्त मण्डलायुक्त डॉ0 लोकेश एम. गुरूवार को प्रयागराज पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के पश्चात मण्डलायुक्त ने गांधी सभागार में आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने आयुक्त कार्यालय स्थित विभिन्न पटलों का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कि एक सप्ताह में सभी पटल प्रभारी फाइलों के रख–रखाव को सुव्यवस्थित कर लें तथा प्रत्येक पत्रावलियों पर नम्बरिंग पट्टिका अंकित करें, साथ ही साथ उन्होंने सभी पटल सहायकों को अपना नाम, पदनाम एवं उनसे सम्बंधित कार्यों के बारे में नेमप्लेट लगाये जाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने सभी पटल सहायकों को एक मास्टर रजिस्टर बनाने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन त्रिभुवन, अपर आयुक्त न्यायिक जयजीत कौर के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

नेपाल सीमा तक फैला था नकली शराब का नेटवर्क, 32 हजार फर्जी ढक्कन

गोरखपुर, (संवाददाता)। जिले में नकली अंग्रेजी शराब के कारोबार पर पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बाँसी पुलिस, एसओजी, सर्विलांस सेल और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 32,472 नकली ढक्कन, 12,740 फर्जी बारकोड (सील रैपर), विभिन्न कंपनियों की 16 बोतल मिश्रित अंग्रेजी शराब, शराब तैयार करने में प्रयुक्त उपकरण और अन्य सामान बरामद किया है। एसपी डॉ अभिषेक महाजन ने प्रेसवार्ता में बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क सिद्धार्थनगर ही नहीं, आसपास के जिलों और नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों तक फैला हुआ था। पुलिस के अनुसार, बुधवार को इटवा रोड स्थित रतन सेन सिंह इंटर कॉलेज के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। इस दौरान बलराम जायसवाल और हरदोई निवासी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। प्रदीप शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में कार्यरत था। गिरफ्तार बलराम जायसवाल की निशानदेही पर पुलिस ने कोइलहवा स्थित सुभाष नगर में किराये के मकान की तलाशी ली। यहां विभिन्न ब्रांडों के नकली ढक्कन, बारकोड, शराब की पैकिंग में प्रयुक्त सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, ढक्कन खोलने के उपकरण और अन्य सामान बरामद हुआ। इसके अलावा संबंधित दुकान से आईबी, आइकॉनिक और आरएस ब्रांड की 16 बोतल संदिग्ध मिश्रित अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई। पूछताछ में बलराम जायसवाल ने पुलिस को बताया कि उसने कोइलहवा में किराये का मकान लेकर नकली ढक्कन और बारकोड का भंडारण कर रखा था। यह सामग्री वह गुरुप्रसाद प्रजापति नामक व्यक्ति से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगाता था। इसके बाद इन्हें सिद्धार्थनगर, आसपास के जिलों और नेपाल सीमा से सटी शराब की दुकानों पर कार्यरत कुछ लोगों को बेच देता था। आरोपी के अनुसार, खाली शराब की बोतलों में दोबारा शराब भरकर उन पर नकली ढक्कन और फर्जी बारकोड लगाकर असली ब्रांड के नाम पर बाजार में बेचा जाता था। इस तरीके से गिरोह लंबे समय से अवैध कमाई कर रहा था। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी मात्रा में नकली और संभावित जहरीली शराब बाजार में पहुंचने से रोक दी गई। साथ ही सरकार को होने वाले लाखों रुपये के राजस्व नुकसान को भी बचाया गया है। मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है ।

दशहरा से पहले बनकर तैयार होगा पादरी बाजार फ्लाईओवर, 98.34 करोड़ की लागत से 570 मीटर लंबा फोरलेन

गोरखपुर, (संवाददाता)। सतत मजबूत हो रहे गोरखपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रृंखला में रोड कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस श्रृंखला में अब एक और फ्लाईओवर की सौगात का नाम जुड़ने जा रहा है। शहर के अति व्यस्त क्षेत्रों में से एक पादरी बाजार चौराहे पर फोरलेन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। दशहरा से पहले यह फ्लाईओवर तैयार होकर संचालन योग्य हो जाएगा। कार्यदायी संस्था अक्टूबर माह में लोकार्पण की तैयारी के हिसाब से काम तेजी से पूरा करा रही है। पादरी बाजार चौराहा शहर के प्रमुख व्यस्त चौराहों में से एक है। बरगदवा–कौआबाग जेल बाईपास पर स्थित यह चौराहा लंबे समय से यातायात के दबाव और जाम के लिए जाना जाता था। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। करीब 570 मीटर की लंबाई में 98.34 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस फोरलेन फ्लाईओवर

का निर्माण कार्य सितंबर 2024 में शुरू हुआ था। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के परियोजना प्रबंधन मिथिलेश कुमार के अनुसार अब तक 92 प्रतिशत कार्य कराया जा चुका है। काम तेजी से कराया जा रहा है। सितंबर अंत तक सभी कार्य पूर्ण कराकर अक्टूबर माह में इसका लोकार्पण कराने की तैयारी है। बरगदवा–कौआबाग जेल बाईपास फोरलेन के पादरी बाजार चौराहा पर फोरलेन फ्लाईओवर बन जाने से ट्रैफिक जाम से स्थानीय लोगों और यात्रियों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही बरगदवा से कौआबाग जेल बाईपास होकर पिपराइच, कप्तानगंज, मेडिकल कॉलेज रोड होते हुए महराजगंज और बरगदवा होते हुए।

मुविवि की बी एड एवं बी एड स्पेशल की प्रवेश परीक्षा

प्रयागराज, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की सत्र 2026– 27 की बी एड एवं बी एड स्पेशल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को प्रदेश के 10 जिलों के 13 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रवेश परीक्षा पूर्वाह्न 10 से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोजन एवं संचालन समिति के समन्वयक की सूचनानुसार प्रवेश परीक्षा के सफल संचालन के लिए कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम के निर्देश पर सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही कोर कमेटी के सदस्य परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहेंगे। यह प्रवेश परीक्षा प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य एवं प्राध्यापकों के देखरेख में संपन्न की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में 7749 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

महेंद्र सिंह खादी बोर्ड के पैनल अधिवक्ता नियुक्त

प्रयागराज, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने विधि विभाग के अंतर्गत महेंद्र सिंह, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया है। धर्मवीर मार्ग सुलेम सरांय निवासी महेंद्र सिंह को उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी विधि द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश पर जारी अधिकार पत्र के माध्यम से यह नियुक्ति दी गई है। अब वह उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले अथवा भविष्य में योजित होने वाले वादों में प्रभावी पैरवी करते हुए।

बसपा विधायक की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, बिलख पड़ीं महिलाएं नम आंखों से कहा अलविदा

वाराणसी, (संवाददाता)। जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह (55) के निधन पर उनके पैतृक गांव खनवर और समर्थकों में शोक छा गया। सुबह से शव यात्रा में शामिल होने के लिए समर्थकों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में समर्थक व नेता खनवर स्थित आवास पर पहुंचे। शव यात्रा में शामिल महिलाएं बिलखती रहीं। उनका कहना था कि विधायक जी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। शव का अंतिम संस्कार बलिया के ब्यासी गंगा घाट पर किया जाएगा। सुबह से खनवर आवास पर अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उमाशंकर सिंह अमर रहे... के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस दौरान

जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह सहित कई नेताओं ने उमाशंकर सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उधर, बृहस्पतिवार को लखनऊ से विधायक का शव रात में पैतृक गांव में पहुंचा तो समर्थकों की भीड़ इतनी थी कि कस्बे के साथ– साथ चौराहे भी जाम हो गए, जब तक सूरज चांद रहेगा, भैया तेरा नाम रहेगा, उमाशंकर सिंह अमर रहे... के नारों के बीच नम आंखों से लोगों ने दर्शन किए। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार की देर रात नई दिल्ली में निधन हो गया था। वे लंबे समय से ब्रेन कैंसर से जूझ रहे थे। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया। वहां से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पार्थिव शरीर को पैतृक गांव खनवर लाया गया।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में हर तरफ हैं खामियां, सीढियों पर पान की पीकें और लैब की टोटियां सूखीं

गोरखपुर, (संवाददाता)। दीक्षांत समारोह के मंच से कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय की खामियां भी एक–एक कर उजागर कर दी। कहा कि हॉस्टलों की सीढिघ्यां पान व मसालों की पीक से लाल हो चुकी हैं। केमिस्ट्री विभाग के लैब में पानी नहीं आ रहा है। परिसर में कई सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। मजीठिया भवन के पास कूड़े का ढेर लगा है। हीरापुरी कॉलोनी में भी गंदगी है। उन्होंने सुधार के लिए समिति बनाने और उसमें छात्रों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। परिसर और हॉस्टलों में गंदगी पर नाराजगी जताते हुए कुलाधिपति ने कहा कि जनभवन की टीम ने हॉस्टलों और विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शिक्षक संघ के सभी कमरों में ताला लगा हुआ है। खेल मैदान भी ठीक नहीं है। विज्ञान संकाय में काफी पुराने पंखे लगे हैं, जिनको बदलने की जरूरत है। हिंदी और जंतु विज्ञान विभागों में पंखे खराब मिले हैं। अलकनंदा छात्रावास में वाई–फाई नहीं है। लाइट की भी समस्या है। एनसी हॉस्टल को निष्प्रयोज्य घोषित कराकर नया भवन बनवाएं। परिसर से प्रशासनिक भवन तक जगह–जगह लगे अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं। एससी–एसटी गर्ल्स हॉस्टल बनने के तीन साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। विश्वविद्यालय में लगे कई फायर सेफ्टी उपकरण एक्सपायर हो चुके हैं। इसे ठीक कराया जाए, जब बेहतर व्यवस्था होगी तभी पढ़ाई का माहौल बनेगा। राज्यपाल ने मंच से बताया कि राजभवन से आई रिपोर्ट के बाद गेस्ट हाउस में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाया था और अपने सामने टीम से तेल और मसाले के नमूने लेने को कहा। इसके अलावा दो छात्रावासों से भोजन के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। एक नमूने की जांच स्थानीय प्रयोगशाला में होगी जबकि दूसरा लखनऊ भेजा जाएगा। ताकि किसी तरह का गोलमाल न हो सके। जांच रिपोर्ट कुलपति को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।